

तंबाकू की कीमतों में वृद्धि

प्रलिस के लिये:

तंबाकू, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO MPOWER, भारतीय तंबाकू बोर्ड, फल-कयूरड वर्जीनिया (FCV), राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

मेन्स के लिये:

तंबाकू सेवन का प्रभाव एवं उपाय, भारत में तंबाकू का सेवन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, विश्व में कैंसर का प्रभाव

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

ब्राज़ील, ज़म्बिाब्वे और इंडोनेशिया में सूखे तथा बेमौसम वर्षा के कारण फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज़ की गई, जिससे आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन करने वाले किसान लाभ की स्थिति में हैं।

- आंध्र प्रदेश में नीलामी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई जसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादक किसान किस प्रकार लाभप्रद स्थिति में है?

- नीलामी की कीमतों में वृद्धि: तंबाकू की कीमतों में लगभग रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई, जो इसकी संभावित कीमतों में 30% की वृद्धि को दर्शाता है।
- विश्व स्तर पर फसल उत्पादन का प्रभाव: व्यापार विश्लेषकों के अनुसार, ब्राज़ील और ज़म्बिाब्वे में फसल उत्पादन में कमी के फलस्वरूप इसके मूल्य में वृद्धि हुई।
 - एक अन्य तंबाकू उत्पादक देश इंडोनेशिया में भी सूखे की स्थिति के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ।
 - चीन एक अन्य महत्वपूर्ण तंबाकू उत्पादक देश है जसिने वैश्विक स्तर पर उत्पादन में हुई कमी से अपने घरेलू सगिरेट उद्योग की रक्षा के लिये तंबाकू निर्यात पर सीमाएँ लगाई, जसिसे तंबाकू उत्पादक देशों में कीमतों में और वृद्धि हुई।
- भारतीय उत्पादकों पर संभावित प्रभाव: तंबाकू निर्यातकों एवं भारतीय तंबाकू बोर्ड के अनुसार, तंबाकू की मांग और उत्पादन के बीच असमानता के कारण आगामी एक वर्ष तक इसकी कीमतों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, जसिसे भारतीय उत्पादकों को लाभ होने की संभावना है।

नोट:

- भारतीय तंबाकू बोर्ड: इसका गठन तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा (4) के तहत 1 जनवरी 1976 को एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।
- बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है और इसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह तंबाकू उद्योग के विकास के लिये उत्तरदायी है।

भारत में तंबाकू उत्पादन के संबंध में प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- कृषि-जलवायु संबंधी तथ्य:
 - तंबाकू मूल रूप से उष्णकटिबंधीय फसल है कति यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जाता है।
 - प्रायः इसके परपिक्व होने के लिये 80 ° F के औसत तापमान के साथ लगभग 100 से 120 दिनों की शीत-मुक्त जलवायु की

आवश्यकता होती है और **प्रतमिह 88 से 125 ममी.** की वर्षा तंबाकू की फसल के लिये आदर्श होती है।

- सापेक्षिक आर्द्रता **सुबह में 70-80%** से लेकर **दोपहर में 50-60%** तक हो सकती है।
- तंबाकू के वभिन्न प्रकारों के इष्टतम विकास के लिये वशिष मृदा और जलवायु की आवश्यकता होती है।
- FCV वभिन्न मृदाओं में उत्पन्न होता है, जसिमें **रेतीली दोमट, लाल दोमट और काली मट्टी सम्मिलित हैं।**

■ आर्थिक महत्त्व :

- वशिष स्तर पर तंबाकू आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फसलों में से एक है।
- भारत में तंबाकू की खेती **कुल कृषियोग्य क्षेत्र का लगभग 0.27%** है, जसिसे वार्षिक लगभग 750 मिलियन किलोग्राम तंबाकू पत्ती का उत्पादन होता है।
- तंबाकू पर लगने वाला **उत्पाद शुल्क**, राजस्व में वार्षिक 14,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, जो देश के कुल कृषि-निर्यात का 4% है।
- **चीन, भारत और ब्राज़ील को वशिष भर में अग्रणी उत्पादकों में आँका गया।**
- जैसे-जैसे **मध्य और उच्च आय वाले देशों** में नयिम सख्त होते जा रहे हैं, तंबाकू कंपनियों, तंबाकू का उत्पादन बढ़ाने के लिये तेज़ी से अफ्रीकी देशों का रुख कर रही हैं।
- **भारत वशिष का तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है।**

■ उत्पादन में विविधता:

- भारत वभिन्न प्रकार की तंबाकू का उत्पादन करता है, जनिमें **फ्लू-क्यूर्ड वर्जीनिया (FCV), बीड़ी, हुक्का, सगार-रैपर, चेरूट, बर्ली, ओरेंटल और अन्य** शामिल हैं।
- भारत के 15 राज्यों में विविध कृषिपरिस्थितिक परिस्थितियों में वभिन्न प्रकार के तंबाकू की खेती की जाती है।
- देश में तंबाकू के उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन मात्रा दोनों में **गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक** शीर्ष 3 स्थानों पर हैं।

■ रोज़गार एवं आजीविका:

- तंबाकू की कृषि भारत में लगभग **36 मिलियन लोगों** को आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, जनिमें किसान, कृषिश्रमिक एवं प्रसंस्करण, वनरिमाण तथा निर्यात क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक शामिल हैं।
- **बीड़ी बनाने से लगभग 4.4 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलता है**, तथा 2.2 मिलियन आदिवासी लोग **तेंदू पत्ता संग्रहण में लगे हुए हैं।**

■ निर्यात बाज़ार एवं प्रतिस्पर्द्धा:

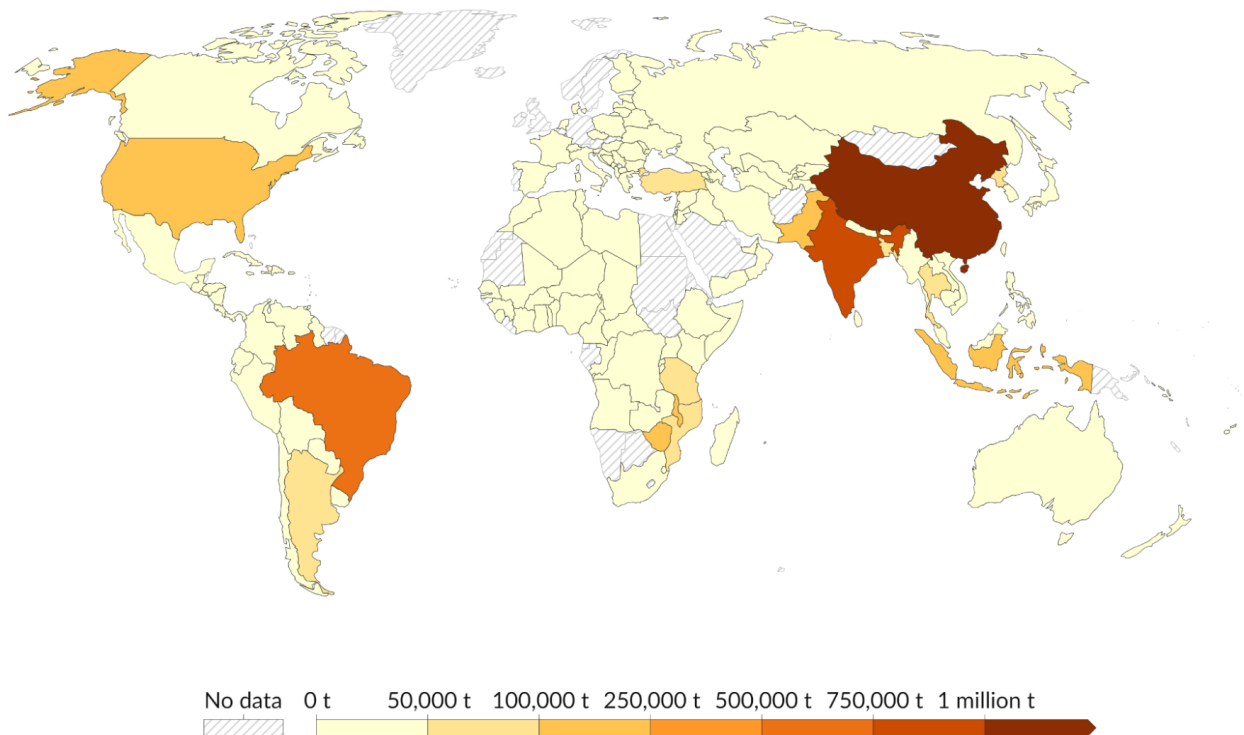
- भारत ने वर्ष 2022-23 में 9,740 करोड़ रुपए की तंबाकू और तंबाकू निर्मिति उत्पादों का निर्यात किया, जसिमें **FCV और बर्ली जैसे सगिरैट-प्रकार के तंबाकू का बड़ा योगदान था।**
- भारतीय FCV तंबाकू के प्रमुख आयातकों में **यूके, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका** शामिल हैं।
- **ब्राज़ील, ज़िम्बाब्वे, तुर्की, चीन और इंडोनेशिया** निर्यात बाज़ार में प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी हैं।
- **वशिष के तंबाकू उत्पादन में 13%** हसिसेदारी के बावजूद, **वैश्विक तंबाकू पत्ती निर्यात में भारत की हसिसेदारी केवल 5% है।**
- भारत, उत्पादित तंबाकू का केवल 30% निर्यात करता है जबकि अन्य प्रमुख तंबाकू उत्पादक देश ब्राज़ील, अमेरिका और ज़िम्बाब्वे अपने उत्पादन का 60-90% निर्यात करते हैं।

■ भारतीय तंबाकू का प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ:

- भारतीय तंबाकू में अन्य तंबाकू उत्पादक देशों की तुलना में भारी धातुओं, तंबाकू वशिषिट नाइट्रोसामाइन (TSNA) एवं कीटनाशक अवशेषों का स्तर न्यूनतम होता है।
- भारत की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों वशिष स्तर पर विविध ग्राहकों की प्राथमिकताओं को पूर्ण करते हुए, वभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पादन की अनुमति देती हैं।
- **कम उत्पादन लागत और निर्यात कीमतों** के मामले में भारत को प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त प्राप्त है, जसि कारण भारतीय तंबाकू को 'कफ़ायती' माना जाता है।

Tobacco production, 2022

Tobacco production is measured in tonnes.



Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023)

Created with Datawrapper

//

तंबाकू द्वारा स्वास्थ्य पर प्रभाव:

■ वैश्विक:

- तंबाकू के कारण **प्रत्येक वर्ष 80 लाख से अधिक लोगों** की मृत्यु हो जाती है, जिसमें अनुमानित 13 लाख गैर-धूम्रपान करने वाले लोग भी शामिल हैं जो अन्य लोगों द्वारा किये जाने वाले धूम्रपान के संपर्क में आते हैं।
- दुनिया के 1.3 अरब तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से लगभग 80% नमिन और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।

■ भारत:

- भारत में वर्ष 2040 तक 2.1 मिलियन **कैंसर** के मामले सामने आने का अनुमान है, जिसमें मुख्य संबंधित कैंसर सबसे प्रचलित रूप है।
 - 80-90% व्यक्ति तंबाकू उपभोक्ता मुँह के कैंसर से पीड़ित हैं।
- **धूम्रपान करने के साथ-साथ धुआँ** रहति तंबाकू सेवन करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सेवन करने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है।
 - धुआँ रहति तंबाकू उत्पादों के उदाहरणों में गुटखा, खैनी और ज़रदा शामिल हैं, जिनका उपयोग चबाने वाले तंबाकू के रूप में किया जाता है।
- भारत में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों में **स्ट्रोक (78%), तपेदिक (65.6%), इस्केमिक हृदय रोग (85.2%), मुँह का कैंसर (38%) और फेफड़ों का कैंसर (16%)** शामिल हैं।
 - भारत में तंबाकू के कारण **13.5 लाख से अधिक मृत्यु होने का अनुमान है** और यह अनुमान लगाया गया है कियदि तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2020 तक भारत में हर वर्ष होने वाली सभी मौतों में से 13% का कारण तंबाकू का सेवन होगा।
- तंबाकू का सेवन **कृष क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी भारत की जीवनशैली** का अभिन्न अंग बना हुआ।

तंबाकू से संबंधित नई पहलें क्या हैं?

■ वैश्विक:

- तंबाकू महामारी से निपटने के लिये [वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन](#) (World Health Organization- WHO) ने वर्ष 2003 में **तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन** (Framework Convention on Tobacco Control) (**WHO FCTC**) को अपनाया।
 - वर्तमान में, 182 देश इस **संधि के पक्षकार हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।**
- **WHO के MPOWER** उपाय **WHO FCTC** के अनुरूप हैं तथा जीवन बचाने एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यय को कम करने में सहायक हैं।
- वैश्विक तंबाकू निगरानी प्रणाली (**Global Tobacco Surveillance System- GTSS**) का उद्देश्य देशों की तंबाकू नियंत्रण उपायों को लागू करने तथा WHO के **FCTC एवं MPOWER** तकनीकी उपायों की निगरानी करने की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
 - इसमें चार सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र करना शामिल है।

■ भारत:

- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP):**
- **सगिरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (वजिजापन का नषिध एवं व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का वनियमन) अधिनियम, 2003:**
 - कानून नाबालगों को उनके द्वारा की जाने वाली तंबाकू उत्पादों की बिक्री को सीमित करता है, सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने से रोकता है और उनके प्रचार, प्रायोजन एवं वजिजापन पर प्रतिबंध लगाता है। यह शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में उनकी बिक्री पर भी रोक लगाता है।
 - इसके अंतर्गत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकों पर नरिदषिट स्वास्थ्य चेतावनियाँ भी आवश्यक हैं।
 - [खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम](#) के तहत तंबाकू या निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, भंडारण एवं वितरण नषिदिध है।
- [इलेक्ट्रॉनिक सगिरेट नषिध अध्यादेश, 2019 का प्रख्यापन](#)

ट्रिपल प्रश्न:

प्रश्न. भारत में तंबाकू उत्पादन के आर्थिक महत्त्व और लाखों लोगों की आजीविका में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। यह स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के साथ कैसे संतुलन बनाता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2012)

1. मृदा की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू-राजस्व का आकलन
2. युद्ध में चलती फरिती तोपों का उपयोग
3. तंबाकू और लाल मरिच की खेती

उपर्युक्त में से कौन-सा/से अंग्रेज़ों की भारत को देन थी/थे?

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 3
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (2008)

सूची-I (बोर्ड)

सूची-II (मुख्यालय)

A. कॉफी बोर्ड

1. बंगलूरु

B. रबर बोर्ड

2. गुंटूर

C. चाय बोर्ड

3. कोट्टायम

कूटः

A B C D

- (a) 2 4 3 1
(b) 1 3 4 2
(c) 2 3 4 1
(d) 1 4 3 2

उत्तर: (b)

रैट होल माइनगि

प्रलिस के लयि:

[अनुच्छेद 371A, रैट-होल माइनगि, कोयला, राषट्रीय हरति न्यायाधकिरण \(NGT\)](#)

मेन्स के लयि:

[अनुच्छेद 371A की सीमाएँ और चुनौतयिँ](#), सतत माइनगि प्रथाएँ, [रैट-होल माइनगि](#), [पर्यावरण प्रदूषण और गरिावट](#), भारतीय हमिलयी क्षेत्र से संबधति चुनौतयिँ ।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में नगालैंड के वोखा ज़िले में [रैट-होल](#) कोयला खदान में आग लगने से छह श्रमकिों की मौत से संबधति मामले में जवाब देने के लयि अधिकारयिों को [राषट्रीय हरति अधकिरण \(National Green Tribunal- NGT\)](#) द्वारा चार सप्ताह का समय दिया गया ।

रैट-होल माइनगि क्या है?

■ परिचय:

- रैट-होल माइनगि, जसि उपयुक्त रूप से कृतक जीवों के बलिों से मलिता-जुलता होने के कारण नामति कयिा गया है, भारत के कुछ हसिंसों, वशिष रूप से मेघालय में प्रचलति कोयला नकिलाने की एक **अवैध और अत्यधकि खतरनाक** वध्ति है
- व्यापक मशीनीकृत आधारति खदानों के वपिरीत, इस वध्ति में **संकीरण, कषैतजि सुरंगों** की खुदाई शामिल है, जनिका आकार इतना होता है कि इनमें केवल एक व्यक्ताकिार्य करने में सकषम होता है
- ये सुरंगें, जनिहें अकसर "रैट होल" कहा जाता है, भूमगित रूप से दस मीटर तक चौड़ी हो सकती हैं ।
- उत्खननकर्त्ता खतरनाक तरीके से उतरने के लयि तात्कालकि मचानों, बाँस की सीढ़यिों या रस्सयिों का उपयोग करते हैं और वे क्लॉस्ट्रोफोबकि, खराब हवादार वातावरण में काम करने के लयि अन्य आदमि उपकरणों के बीच फावड़े तथा गैती का उपयोग करते हैं ।
- खदानों से नकिले गए कोयले को फरि इन संकीरण मार्गों से वापस लाया जाता है, जसिसे पूरी प्रक्रयिा अवशि्वसनीय रूप से **सेजोखमिपूरण और जटलि** हो जाती है ।

■ प्रकार:

- **साइड-कटगि प्रक्रयिा:** संकीरण सुरंगों को साइड-कटगि प्रक्रयिा में पहाड़ी ढलानों में खोदा जाता है, जहाँ श्रमकि मेघालय की पहाड़यिों में आमतौर पर 2 मीटर से कम संकरी कोयले की सीम का पता लगाने के लयि प्रवेश करते हैं ।
- **बॉक्स-कटगि:** बॉक्स-कटगि का उपयोग करके कोयला नकिलते समय, एक आयताकार प्रवेश द्वार बनाया जाता है तथा एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है, और फरि रैटहोल के आकार की कषैतजि सुरंगें तैयार की जाती हैं ।

■ भौगोलिक वसितार:

- हालाँकि रैट-होल माइनरि मुख्य रूप से मेघालय में प्रचलित है, लेकिन भारत के अन्य [पूर्वोत्तर राज्यों](#) में भी रैट-होल माइनरि की जाती है।
- इसे कोयले की पतली परत वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर माइनरि तकनीकों के लिये अनुपयुक्त है।

■ रैट होल माइनरि के कारण:

- गरीबी: आजीविका के सीमिति वकिल्पो के साथ स्थानीय [जनजातीय जनसंख्या](#) अक्सर जीवित रहने के साधन के रूप में रैट-होल माइनरि का सहारा लेती है।
 - जोखिमों के बावजूद, निकाले गए कोयले को बेचने से प्राप्त होने वाली त्वरित नकदी उन लोगों के लिये एक आकर्षक विकल्प बन जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- भू-स्वामित्व:
 - संदिग्ध भूमि स्वामित्व द्वारा वनियमिति खदानों की स्थापना करने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, अवैध ऑपरेटरों के लिये कमियों का लाभ उठाने तथा अपनी गतिविधियों को जारी रखने के अवसर प्रदान करते हैं।
- कोयले की मांग: कोयले की वैध और अवैध दोनों प्रकार की निरंतर मांग, रैट-होल माइनरि की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।
 - अवैध रूप से निकाले गये कोयले का विक्रय करने हेतु बच्चों लिये और अवैध व्यापारी एक बाज़ार का निर्माण करते हैं, यह चक्र निरंतर जारी रहता है जिससे खनिकों के लिये जोखिमपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

■ मुद्दे:

- जीवन को जोखिम: संकरी सुरंगों के ढहने का खतरा रहता है, जिससे अक्सर खनिक भूमि के अंदर फँस जाते हैं।
 - खदानों में ऑक्सीजन कमी के कारण खनिकों का दम घुटता है और उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उनको अक्सर दुर्घटनाओं, चोटों तथा जीवन के लिये खतरा उत्पन्न करने वाली बीमारियों का जोखिम बना रहता
- पर्यावरणीय क्षति: पहुँच प्राप्त करने हेतु भूमि साफ करने के लिये [वनों की कटाई](#), अकस्मात खुदाई से [मृदा अपरदन](#) और अनुचित अपशिष्ट निपटान के कारण [जल प्रदूषण](#) इस प्रक्रिया के कुछ स्थायी पर्यावरणीय परिणाम हैं।
 - रैट होल की खदानें [अम्लीय अपवाह का भी कारण](#) बनती हैं, जसिसे [एसडि माइन ड्रेनेज \(AMD\)](#) के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है एवं प्रभावित जल निकायों में जैवविविधता हानि होती है।



सलिक्यारा (उत्तराखंड) सुरंग का ढहना:

- नवंबर 2023 में [उत्तराखंड में सुरंग](#) ढहने से 41 श्रमिक फँस गए थे। इस दुष्कर परिस्थिति में उनके सफल बचाव के लिये एक [प्रतिबंधित तकनीक](#), रैट-होल माइनरि का प्रयोग किया गया।
- खनिकों ने सफलतापूर्वक एक संकीर्ण मार्ग तैयार किया, जिससे सभी 41 श्रमिकों को बचाया जा सका। यह घटना दुष्कर परिस्थितियों में त्वरित बचाव के लिये इस तकनीक की वशिष्ट क्षमता का एक उदाहरण है।
- हालाँकि, यह तकनीक एक [उच्च जोखिम वाली तकनीक](#) है। परंतु इस घटना से सुरक्षा एवं वनियमिति माइनरि प्रक्रियाओं के महत्त्व पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

रैट-होल माइनरि को वनियमिति करने के उपाय क्या हैं?

■ नगालैंड में रैट-होल माइनरि का वनियमिति:

- नगालैंड में 492.68 मिलियन टन कोयला भंडार छोटे, अनियमित क्षेत्रों में बखिरा हुआ है, जिसके कारण बड़े स्तर पर माइनरि संचालन की अव्यवहारिकता के कारण 2006 की [नगालैंड कोयला माइनरि नीति](#) के तहत रैट होल माइनरि की अनुमति दी गई है।

- रैट-होल माइनगि लाइसेंस, जनिहें छोटे पॉकेट डिपॉज़िट लाइसेंस के रूप में जाना जाता है, वशिष रूप से व्यक्तगित भूमि मालिकों को सीमति अवधि और वशिषिट शर्तों के साथ प्रदान कयि जाते हैं।
- रैट-होल माइनगि हेतु पर्यावरणीय अनुपालन सुनश्चिति करने हेतु वन एवं पर्यावरण जैसे वभिगों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, फरि भी सरकारी अनुमति तथा योजनाओं के बावजूद अवैध माइनगि संचालन होता रहता है।
- अनुच्छेद 371A और नगालैंड में रैट-होल माइनगि पर नयितरण:
 - **अनुच्छेद 371A** नगालैंड में सरकारी वनियमन को जटलि बनाता है, जसिसे छोटे स्तर पर माइनगि की नगिरानी बाधति होती है, वशिषतः व्यक्तगित भूमि मालिकों द्वारा।
- उपाय
 - **आजीविका के वकिल्पः** स्थायी आय स्रोत प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें **कौशल विकास कार्यक्रम, पर्यटन या हस्तशलिप** जैसे वैकल्पिक उद्योगों को बढ़ावा देना एवं सूक्ष्म-वित्तपोषण के अवसर उत्पन्न करना शामिल है।
 - वतितीय सुरक्षा के लयि अन्य सुरक्षति एवं सुगम साधनों को प्रदान कर, समुदायों को रैट-होल माइनगि न करने के लयि प्रोत्साहति कयि जाए।
 - **सतत माइनगि प्रक्रयिः** पतली परतों से कोयला नकिलने के लयि उपयुक्त वैकल्पिक, सुगम माइनगि तकनीकों की खोज करना आवश्यक है।
 - **बोर्ड और पलिर माइनगि** अथवा छोटे स्तर पर मशीनीकृत माइनगि जैसी तकनीकों पर अनुसंधान एवं अनुप्रयोग से सुरक्षति तथा अधिक कुशल माइनगि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
 - **सख्त प्रवर्तनः** वधिकि प्रवर्तन को सशक्त करना एवं अवैध माइनगि में संलग्न व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करना एक उचति उपाय के रूप में कार्य कर सकता है।
- वधिकि परदृश्यः
 - **अंतर्राष्ट्रीय संदर्भः** रैट-होल माइनगि का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने हेतु कसी वशिषिट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव है।
 - हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय नयिमों में **माइनगि की सतत वधियिों को बढ़ावा** देने के साथ-साथ श्रमिक सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जसिसे संबद्ध सदस्य देश अप्रत्यक्ष रूप से उक्त प्रथाओं को अपनाने के लयि प्रभावति होते हैं।
 - **भारतीय संदर्भः** इस प्रथा के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, **राष्ट्रीय हरति अधकिरण (National Green Tribunal- NGT)** ने वर्ष 2014 में भारत में रैट-होल माइनगि पर प्रतबिंध लगाया।
 - **संबंधति सरकारी पहलः**
 - रैट-होल माइनगि पर NGT का प्रतबिंध, हालाँकि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, यह इस प्रथा को समाप्त करने की प्रतबिद्धता को दर्शाता है।
 - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम (मनरेगा)** जैसी वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का उद्देश्य रैट होल माइनगि पर नरिभर लोगों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करना है।

नश्किर्षः

- संबद्ध वषिय में एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जैसा ककिई देशों द्वारा कयि गया है, रैट-होल माइनगि पर पूर्ण प्रतबिंध एक नश्चिति समाधान प्रदान करता है।
- हालाँकि, लघु पैमाने के माइनगि पर आर्थिक रूप से नरिभर क्षेत्नों के लयि सुरक्षति माइनगि वकिल्पों को वकिसति करने और लागू करने पर ध्यान केंद्रति कयि जाना चाहयि।
- यंत्रचालति, लघु पैमाने के माइनगि उपकरणों के अनुसंधान और विकास में नविश करना, एक सुरक्षति एवं अधिक कुशल समाधान प्रदान कर सकता है। इसके अतरकिर्त, भवषिय की संभावति त्रासदयिों की रोकथाम के लयि सुदृढ़ सुरक्षा प्रशक्षण कार्यक्रम और नयिमों का सख्त कार्यान्वयन आवश्यक है।

दृष्टिभेन्स प्रश्नः

प्रश्न. भारत में रैट-होल माइनगि से संबंधति पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी चतिओं की वविचना कीजयि। सतत् माइनगि प्रथाओं को सुनश्चिति करते हुए इन मुद्दों के समाधान के उपायों का सुझाव दीजयि

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. "प्रतकिल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला माइनगि विकास के लयि अभी भी अपरहार्य है"। वविचना कीजयि। (2017)

प्रलम्बित के लिये:

जलवायु परिवर्तन, [जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना \(NAPCC\)](#), [राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान \(NDC\)](#), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC), [जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना \(SAPCC\)](#)

मेन्स के लिये:

क्लाइमेट माइग्रेशन ([जलवायु प्रवासन](#)) का मुद्दा और संभावित उपाय

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [जलवायु प्रवासन](#) (जलवायु परिवर्तनों के कारण प्रवास) की समस्या ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है, परंतु फरि भी वशिष्ठ [मैंगीर मौसम आपदाओं](#) के कारण अपने स्थायी आवासों को छोड़ने के लिये बाध्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचे का अभाव है।

- यह गंभीर अंतर बढ़ते वसिस्थापन के समय में एक सुभेद्य जनसांख्यिकी को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बनिा छोड़ देता है।

जलवायु प्रवासी कौन हैं?

- **?????:**
- [इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन \(IOM\)](#) के अनुसार, "जलवायु प्रवासन" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या जनसमूह की गतिविधियों से है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन अथवा आकस्मिक या क्रमिक पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अपने आवास की छोड़ने के लिये बाध्य होते हैं।
- यह गतिविधि अस्थायी या स्थायी हो सकती है एवं किसी देश के भीतर या बाहर भी हो सकती है।
- यह परिभाषा इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि जलवायु प्रवासी मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अपना स्थायी आवास छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।
- **जलवायु प्रवासन के कारण:**
- **आकस्मिक आपदाएँ एवं वसिस्थापन:**
- **आंतरिक वसिस्थापन:** मानवीय मामलों के समन्वय के लिये [संयुक्त राष्ट्र कार्यालय \(OCHA\)](#) की रिपोर्ट इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि [बाढ़](#), [तूफान](#) और [भूकंप](#) जैसी आकस्मिक आपदाएँ अक्सर उनके आंतरिक वसिस्थापन का कारण बनती हैं।
- लोग अपने देशों में सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, परंतु [बुनियादी ढाँचे एवं आजीविका](#) के नष्ट हो जाने के कारण उनका स्थायी आवास क्षेत्रों में लौटना कठिन हो सकता है।
- **आपदाएँ और संवेदनशीलता:** [संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी \(UNHCR\)](#), इस तथ्य पर दबाव डालती है कि आपदाएँ अक्सर सुभेद्य जनसांख्यिकी को प्रभावित करती हैं।
- संसाधनों की कमी या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाली इस जनसांख्यिकी के वसिस्थापित होने एवं संघर्ष करने की संभावनाएँ अधिक हैं।
- **धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएँ एवं प्रवासन:**
 - **पर्यावरणीय क्षरण एवं आजीविका:** [IOM](#) की रिपोर्ट है कि सूखा, मरुस्थलीकरण तथा लवणीकरण जैसी धीमी गति से घटित होने वाली आपदाएँ भूमि और जल संसाधनों को वनिष्ट कर सकती हैं।
 - इससे लोगों के लिये अपनी आजीविका चला पाना दुष्कर होता है तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में प्रवासन करना पड़ता है।
- **समुद्र के स्तर में वृद्धि एवं तटीय समुदाय:** [जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल \(IPCC\)](#) की रिपोर्ट में समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय क्षेत्रों में निवास कर रहे समुदायों को संकट होने की चेतावनी दी गई है। इससे लोगों घर और खेत जलमग्न हो जाएंगे, जिससे स्थायी वसिस्थापन हो सकता है।
- **जलवायु प्रवासन की जटिलताएँ:**
- **मिश्रित कारण:** [संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग \(UNDESA\)](#) स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रवासन के लिये कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है।
- **गरीबी**, राजनीतिक अस्थिरता एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव, आपदाएँ आने पर नागरिकों को प्रवासन के लिये विवश करती हैं।
- **डेटा अंतराल और नीतिगत चुनौतियाँ:** [वशिष्ठ बैंक](#) जलवायु प्रवासन का स्पष्ट डेटा निर्धारित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
- इससे वसिस्थापित लोगों एवं सुभेद्य समुदायों को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी नीतियाँ विकसित करना कठिन हो जाता है।

जलवायु शरणार्थियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रयास:

- **वर्ष 1951:** जनिवा अभिसमय शरणार्थियों की कानूनी परिभाषा देता है। इसमें जलवायु आपदाओं को शरण लेने के आधार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है
 - हालाँकि, वर्ष 2019 में [शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त](#) का कहना है कि जनिवा अभिसमय को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है।
- **वर्ष 1985:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पहली बार सामान्यतः पर्यावरण शरणार्थियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो

- "पर्यावरणीय व्यवधान" के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से अपने पारंपरिक निवास स्थान को छोड़ने के लिये मजबूर होते हैं।
- **वर्ष 2011:** नॉर्वे में जलवायु परिवर्तन और वसि्थापन पर आयोजित हुए नानसेन सम्मेलन में 10 सदिधांत तैयार किये गए हैं।
 - **वर्ष 2013:** यूरोपीय आयोग यूरोप में जलवायु-प्रेरित प्रवासन को कम महत्त्व देता है।
 - **वर्ष 2015:** पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वसि्थापन को रोकने, कम करने और संबोधित करने के दृष्टिकोण की सफिराशि करने के लिये एक कार्यबल का आह्वान किया गया
 - **वर्ष 2018:** हालाँकि, जलवायु से प्रभावित शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल किया गया है, कति इसके लिये किसी भी सरकार ने कोई ठोस प्रतबिद्धता नहीं बनाई है।
 - **वर्ष 2022:** प्रवास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रसितरीय घोषणा से जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से प्रभावित लोगों को हॉर्न और पूरवी अफ्रीका क्षेत्रों में सीमाओं के पार सुरकषति रूप से जाने की अनुमतमिलित है।
 - **वर्ष 2023:** प्रशांत-द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों की सीमा-पार आवाजाही को अनुमतदिने के लिये एक रूपरेखा पर सहमत हैं।

जलवायु प्रवासियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **संकटपूर्ण आजीविका:**
 - कौशल और संपत्तिका हानि: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने चेतावनी दी है कवसि्थापन के कारण जलवायु प्रवासियों को अक्सर अपने कौशल और संपत्तिका हानि होती है।
 - इससे लोगों के लिये अपरचिति वातावरण में अपनी आजीविका और दूसरा रोजगार प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
 - अनौपचारिक कार्य और शोषण: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) की रपिर्ट बताती है कजलवायु प्रवासी अक्सर कम वेतन और खराब कामकाजी परसि्थितियों वाले अनौपचारिक कार्य क्षेत्रों में चले जाते हैं।
 - अपनी अनसिचिति स्थिति के कारण वे शोषण के प्रतअधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
- **एकीकरण और सामाजिक चुनौतियाँ:**
 - सेवाओं तक पहुँच का अभाव: वशि्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला कजलवायु प्रवासी अक्सर अपने नए स्थानों में स्वास्थ्य देखभाल, शकिषा और आवास जैसी आधारभूत सेवाओं तक पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं।
 - यह इनके सामाजिक बहिषकार और हाशिये पर रखे जाने का कारण बन सकता है।
 - सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ: IOM जलवायु प्रवासियों को नई संस्कृतियों और भाषाओं को अपनाने में आने वाली कठनाइयों पर ज़ोर देता है।
 - यह नए समुदायों में एकीकृत होने की उनकी कषमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **कानूनी स्थिति और सुरकषा:**
 - सीमति कानूनी ढाँचा: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की रपिर्ट बताती है कजलवायु प्रवासियों की सुरकषा के लिये कोई स्पष्ट कानूनी ढाँचा नहीं है।
 - वे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी का दर्ज़ा पाने के लिये योग्य नहीं हैं।
 - राज्यवहिीन होने का बढ़ता जोखमि: जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ का दावा है कजलवायु परिवर्तन से प्रेरित वसि्थापन राज्यवहिीनता का कारण बन सकता है, वशिष रूप से उन लोगों के लिये जो देशीय सीमाओं को पार करते हैं।
 - वर्ष 2021 में वशि्व बैंक ने अपनी ग्राउंडसवेल् रपिर्ट में अनुमान लगाया कवर्ष 2050 तक, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण वशि्व भर में लगभग 216 मिलियन लोग आंतरिक रूप से वसि्थापित हो जाएंगे।
- **मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:**
 - अभघात और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: WHO वसि्थापन और कषतिके कारण जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रवासियों द्वारा अनुभव किये जाने वाले मनोवैज्ञानिक व्यथा एवं अभघात (Trauma) पर प्रकाश डालता है।
 - आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुँच सीमति होती है, जसिसे उनके स्वास्थ्य का संघर्ष और भी बढ़ जाता है।
 - स्वास्थ्य जोखमिों के प्रतसुभेद्यता में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नए स्थानों परस्वास्थ्य जोखमिों, जैसे संक्रामक रोग अथवा खराब मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह वशिष रूप से बच्चों और वृद्धजनों के लिये चतिजनक है।

क्लाइमेट माइग्रेशन के मुद्दे के समाधान से संबंधित नीतियों की सीमाएँ क्या हैं?

- **प्रवासन के लिये वैश्विक समझौता:** हालाँकि, यह समझौता मानव प्रवासन को जलवायु परिवर्तन के कारक के रूप में स्वीकार करता है कति इसमें जलवायु शरणार्थियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे परस्वरसम्मतिस्थापति करने में होने वाली कठनाई को दर्शाता हो।
- **क्षेत्रीय संधियों और घोषणाएँ:** कंपाला घोषणा जैसे क्षेत्रीय समझौतों में सामान्यतः क्लाइमेट रेफ्यूजी की स्पष्ट मान्यता का अभाव होता है, जो अधिक व्यापक वधिकि ढाँचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **क्लाइमेट रेफ्यूजी की पहचान:** जलवायु-प्रेरित वसि्थापन की जटलि प्रकृति को देखते हुए, प्रमुख चुनौतियों में से एकजलवायु परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों अथवा समुदायों को शरणार्थियों के रूप में पहचानना और वर्गीकृत करना शामिल है।
- **सामूहिक वसि्थापन:** जलवायु परिवर्तन मुख्य तौर पर समग्र समुदायों अथवा राष्ट्रों को प्रभावित करता है, जसिके लिये सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

क्लाइमेट माइग्रेशन की समस्या के समाधान के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- बांग्लादेश जैसे देश अपने निवासियों को समुद्र के बढ़ते स्तर और तूफान से बचाने के लिये तटीय तटबंधों एवं बाढ़ प्रतशिधी बुनयादी ढाँचे में निवेश

- कर रहे हैं।
- **फ़िजी** जैसे द्वीप राष्ट्र समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण, जीवन योग्य अनुकूल भूभाग को ऊँचा करने जैसे **नवीन उपाय** तलाश रहे हैं।
 - समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण **करिबिती** अपनी आबादी के नयोजित स्थानांतरण के विकल्प तलाश रहे हैं।
 - इसमें नई बस्तियों में **भूमि अधिग्रहण, सांस्कृतिक संरक्षण** और आजीविका के अवसरों पर सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है।
 - **भारत और वियतनाम** जैसे देशों में बाढ़, चक्रवात और अन्य खराब मौसम की घटनाओं से बचाव के लिये **त्वरित चेतावनी प्रणालियाँ** कार्यान्वित की गई हैं।
 - ये प्रणालियाँ समुदायों को संवेदनशील क्षेत्रों को खाली करने और हताहतों तथा वसिस्थापन को कम करने में सहायता प्रदान करती हैं।
 - **प्रलंबित (लंबे समय तक जारी रहने वाला) वसिस्थापन पर कंपाला घोषणा** अफ्रीकी देशों द्वारा संघर्ष की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से वसिस्थापित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनाया गया एक क्षेत्रीय ढाँचा है।
 - यह क्लाइमेट माइग्रेशन के संबंध में क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक मॉडल प्रदान करता है।
 - **इथियोपिया जैसे देश किसानों को मौसम के बदलाव के अनुकूल ढलने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिये सूखा प्रतिरोधी फसलों तथा सिंचाई प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं।**
 - इससे भोजन की कमी के कारण होने वाले वसिस्थापन का जोखिम कम हो जाता है।
 - **अनुकूलन उपायों के अन्य उदाहरण:**
 - पेसफिक आइलैंड क्लाइमेट मोबिलिटी फ्रेमवर्क: यह फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिये प्रशांत द्वीप देशों के बीच वधिसिम्मत आगमन की सुविधा प्रदान करता है, जो क्षेत्रीय सहयोग और अनुकूलन के लिये एक मॉडल प्रदान करता है।
 - तुवालु-ऑस्ट्रेलिया संधि: यह संधि तुवालु और ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई जिसका उद्देश्य जलवायु संबंधी खतरों का सामना करने वाले तुवालु के निवासियों को निवास प्रदान करना है जो क्लाइमेट माइग्रेशन चुनौतियों से निपटने के लिये द्विपक्षीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

भारत की जलवायु परिवर्तन शमन हेतु नई पहलें क्या हैं?

- [जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना](#) (National Action Plan on Climate Change- NAPCC)
- [राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान](#) (Nationally Determined Contributions- NDC)
- [राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष](#) (National Adaptation Fund on Climate Change- NAFCC)
- [State Action Plan on Climate Change \(SAPCC\)](#)
- [जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना](#) (State Action Plan on Climate Change- SAPCC)

आगे की राह

- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:**
 - **IPCC ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये **आक्रामक शमन रणनीतियों** के महत्त्व पर जोर देता है।
 - **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UN Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)** समुदायों को जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनने और वसिस्थापन जोखिमों को कम करने में सहायता करने के लिये अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा देता है।
- **आपदा की तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण:**
 - **आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UN Office for Disaster Risk Reduction- UNDRR)** आकस्मिक आपदाओं के कारण होने वाले वसिस्थापन को कम करने के हेतु आपदा तैयारी योजनाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जोखिम कम करने के उपायों के महत्त्व पर जोर देता है।
- **कानूनी ढाँचे और सुरक्षा तंत्र:**
 - **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UN Refugee Agency- UNHCR)** और IOM जलवायु प्रवासियों की सुरक्षा के लिये कानूनी ढाँचा विकसित करने का समर्थन करते हैं।
 - इसमें **शरणार्थी शब्द की परिभाषा को और व्यापक बनाना** या जलवायु परिवर्तन के कारण वसिस्थापित लोगों के लिये संरक्षण की एक नई श्रेणी बनाना शामिल हो सकता है।
- **नयोजित पुनर्वास और पुनर्स्थापन:**
 - **वर्ल्ड बैंक की ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट** द्वारा यह माना गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ समुदाय स्थायी रूप से रहने योग्य नहीं रह जाएंगे।
 - इन चरम मामलों में नयोजित स्थानांतरण और पुनर्वास कार्यक्रम आवश्यक हो सकते हैं।
- **सतत विकास एवं जलवायु-स्मार्ट कृषि में निवेश:**
 - **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UN Department of Economic and Social Affairs- UNDESA)** **सतत विकास और जलवायु-स्मार्ट कृषि में निवेश** के महत्त्व पर जोर देता है।
 - इससे लोगों के लिये जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं और प्रवासन की आवश्यकता में कमी आ सकती है।
- **श्रमिक प्रवासन योजनाएँ:**
 - जलवायु-वसिस्थापित जनसंख्या के लिये अनुकूलन उपाय के रूप में देशों के मध्य श्रम प्रवास को प्रोत्साहित करने से आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में जलवायु प्रवासन की चुनौतियों और नीतिगत प्रभावों पर चर्चा कीजिये। सरकार प्रवासन को प्रेरित करने वाली पर्यावरणीय चर्चाओं को संबोधित करते हुए जलवायु प्रवासियों की सुरक्षा एवं कल्याण कैसे सुनिश्चित कर सकती है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

मेन्स:

प्रश्न. बड़ी परियोजनाओं के नयोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्त्वपूर्ण पारस्थितिक संघात है, जिस पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिये सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. बड़ी परियोजनाओं के नयोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्त्वपूर्ण पारस्थितिक संघात है, जिस पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिये सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016)

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि

प्रलम्ब के लिये:

[राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति \(NHP\)](#), [आयुष्मान भारत PMJAY](#), [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन](#), [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग](#)

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) डेटा के नषिकर्ष, भारत में स्वास्थ्य नधि में हुई वृद्धि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौतियाँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के आँकड़ों के अनुसार [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) के अनुपात के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान 63% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA):

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (NHA) अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरेट (NHATS) का दर्जा दिया गया था।
- NHA अनुमान [वर्ष स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) द्वारा वकिसति स्वास्थ्य लेखा प्रणाली, 2011 के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक के आधार पर एक लेखांकन ढाँचे का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
- ये अनुमान न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय हैं, बल्कि नीति निर्माताओं को देश के विभिन्न स्वास्थ्य वित्तपोषण संकेतकों में प्रगतिकी निगरानी करने में भी सक्षम बनाते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र

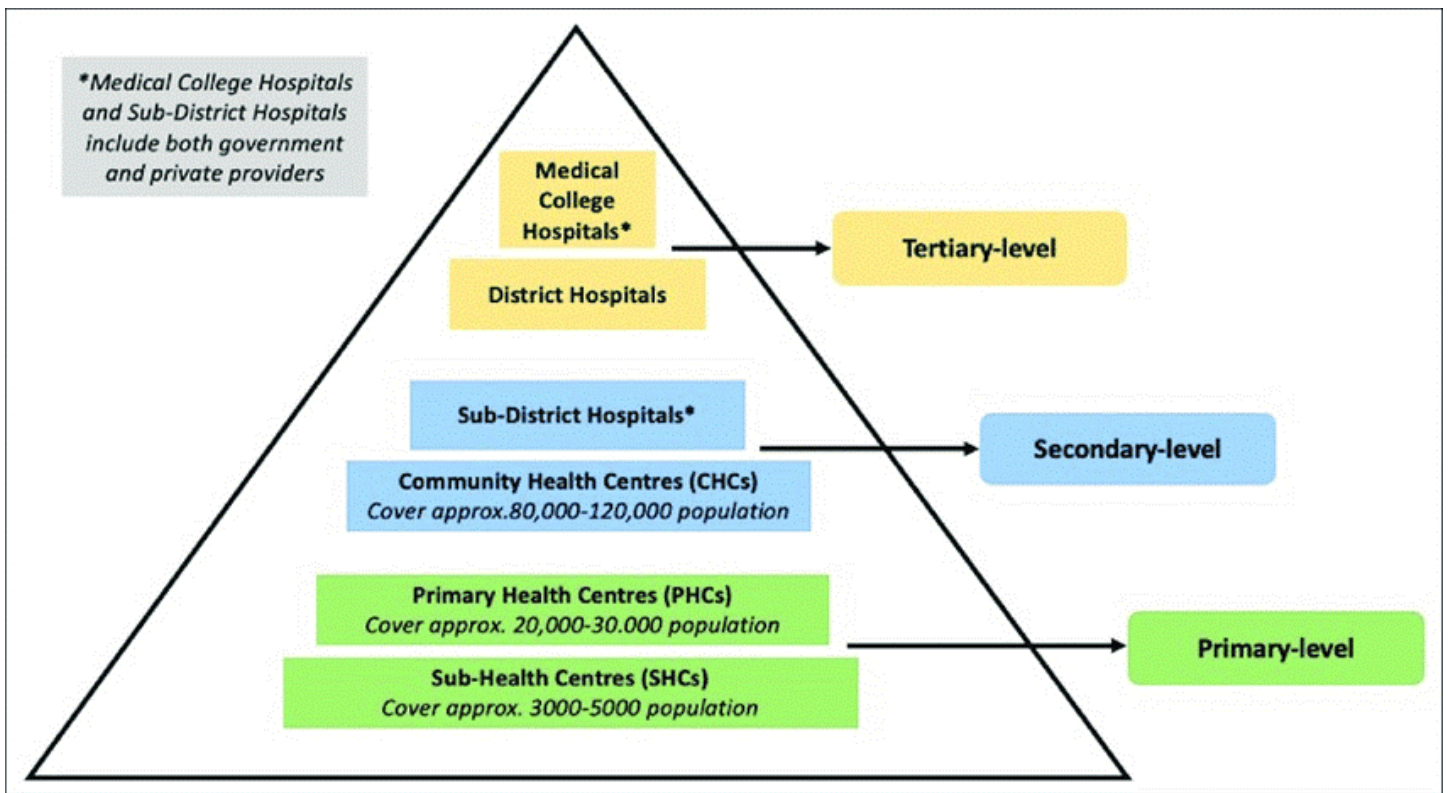
- इसकी स्थापना वर्ष 2006-07 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन (NRHM) के तहत तकनीकी सहायता के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका अधिदेश राज्यों को तकनीकी सहायता जुटाने और प्रदान करने तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के लिये क्षमता निर्माण में नीति और रणनीति विकास में सहायता करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts- NHA) डेटा के नषिकर्ष क्या हैं?

- **स्वास्थ्य सेवा में बढ़ता सरकारी नविश:**
 - यह वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **सरकारी स्वास्थ्य व्यय** (Government Health Expenditure- GHE) में उल्लेखनीय वृद्धि (1.13% से 1.84%) के रूप में परिलक्षित होता है।
 - स्वास्थ्य पर **प्रतिव्यक्ति सरकारी व्यय** भी इसी अवधि में लगभग तीन गुना हो गया है।
 - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** (National Health Policy- NHP) का लक्ष्य हर किसी को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच प्रदान करना है। इसमें वर्ष 2025 तक **सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव** है।
- **सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा योजनाओं पर ध्यान देना:**
 - **आयुष्मान भारत PMJAY** जैसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में नविश तेज़ी से बढ़ा है (वर्ष 2013-14 से 4.4 गुना वृद्धि)।
 - स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च की हसिसेदारी में भी वृद्धि हुई है, जो एक अधिक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की ओर परिवर्तन का प्रदर्शन करता है।
- **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में कमी :**
 - **OOPE** (स्वास्थ्य सेवा पर व्यक्तियों द्वारा सीधे खर्च किया गया धन) में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच 62.6% से घटकर 39.4% हो गई है।
 - **OOPE की कमी में योगदान देने वाले कारक:**
 - **आयुष्मान भारत PMJAY** जैसी योजनाएँ लोगों को बना किसी वित्तीय बोझ के गंभीर बीमारियों के इलाज तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करती हैं।
 - **सरकारी सुविधाओं का बढ़ता उपयोग, नशुल्क एम्बुलेंस सेवाएं तथा अन्य पहलें** OOPE को कम करने में योगदान देती हैं।
 - **आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAM)** पर नशुल्क दवाइयों और नदान की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवा की लागत को और कम करती है।
- **आवश्यक दवाईयों के मूल्य वनियमन पर फोकस:**
 - **जन औषधिकेंद्र** कफायती जेनेरिक औषधियाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध कराते हैं, जिससे वर्ष 2014 से अब तक नागरिकों को अनुमानित 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
 - **सर्टेंट और कैंसर की दवाओं जैसी आवश्यक दवाओं के मूल्य को वनियमित करने** से बचत में और अधिक वृद्धि हुई है (अनुमानित 27,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष)।
- **स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सशक्त बनाना:**
 - सरकारी व्यय में वृद्धि केवल स्वास्थ्य सेवाओं को लक्षित करती है, बल्कि इसमें जलापूर्ति और स्वच्छता (**जल जीवन मशिन** और **स्वच्छ भारत मशिन** के माध्यम से) में नविश भी शामिल है।
- **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में नविश:**
 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मशिन** जैसी योजनाएँ एम्स (AIIMS) और ICU सुविधाओं सहित चिकित्सा अवसंरचना को मजबूती प्रदान कर रही हैं।
 - स्थानीय निकायों के लिये स्वास्थ्य अनुदान में वृद्धि से **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली** सशक्त हुई है।

नोट:

- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) वह धनराशि है जिनका भुगतान स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के समय परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- इसमें किसी भी सार्वजनिक या निजी बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों शामिल नहीं हैं।



भारत में बढ़े हुए हेल्थकेयर फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- बेहतर सुविधाओं तक पहुँच में असमानता:
 - लंबी यात्रा में लगने वाला समय और विशेषज्ञों तक सीमिति पहुँच ग्रामीण जनसंख्या के लिये सामान्य समस्याएँ हैं, जिससे इनके नदिन में वलिनब हो सकता है तथा स्वास्थ परणाम प्रभावति हो सकते हैं।
 - नीतिआयोग की वर्ष 2021 की रपिरट, शहरी क्षेत्सों (1:400) के पक्ष में डॉक्टर-रोगी अनुपात (1:1100) वषिम वतिरण के साथ महत्त्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ प्रोफाइल 2022 से पता चलता है कि मिधुमेह और हृदय रोग जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCD) में वृद्धि हुई है, जनिका इलाज अत्यधिक महंगा है।
- नधियों का दुरुपयोग और अक्षमताएँ:
 - नौकरशाही की अक्षमताएँ, कुप्रबंधन और संभावति भ्रष्टाचार धन को उसके इच्छति लाभार्थियों तक पहुँचने से रोकने के मुख्य कारक हैं।
 - भारत के नयितरक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वर्ष 2018 की रपिरट में सरकारी अस्पतालों में बढ़े हुए बलियों और अनावश्यक प्रक्रियाओं के मामलों की पहचान की गई है।
- मानव संसाधन बाधाएँ:
 - डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ सेवा पेशवरों की कमी अक्सर अधिक काम करने वाले कर्मचारियों, देखभाल की गुणवत्ता से समझौता करने तथा लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का कारण बनती है।
 - भारत में डॉक्टर-नर्स अनुपात वर्तमान में विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसति 4:1 की तुलना में 1:1 के है।
 - इसके अतिरिक्त, वर्तमान स्थिति में, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक-रोगी अनुपात 1 ~11000 है, जो कि WHO की अनुशंसा 1:1000 से काफी अधिक है।

आगे की राह

- उच्च वेतन, बेहतर आवास सुविधाओं और करियर में प्रगतिके अवसर जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने वाले कार्यक्रमों के साथ कफायती अस्पतालों और क्लीनिकों का निर्माण करके ग्रामीण स्वास्थ देखभाल के बुनियादी ढाँचे में नविश करना।
- रोगी देखभाल के लिये धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रभावी नगिरानी प्रणाली और सख्त नधियों की आवश्यकता है।
- ऐसे अस्पतालों में जहाँ कर्मचारियों की संख्या कम है, सरकारी चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने और रोगी-उन्मुख सुविधाओं में सुधार करने से रोगी की उचित देखभाल हो सकती है तथा उपचार के लिये प्रतीक्षा समय कम हो सकता है।

- स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देने एवं रोग का शीघ्र पता लगाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से नविकरक स्वास्थ्य देखभाल में नविश से भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल लागत कम हो सकती है।
 - जनता को स्वस्थ खान-पान की आदतों के वषिय में शक्ति करणे एवं नयिमति जाँच को प्रोत्साहति करने पर खर्च बढ़ाने से, संभावति रूप से महँगे इलाज वाली पुरानी बीमारियों से पीड़ति व्यक्तियों की संख्या में कमी आ सकती है।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधति हालिया सरकारी पहल क्या हैं?

- [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन](#)
- [आयुषमान भारत](#)
- [प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(AB-PMJAY\)](#)
- [राष्ट्रीय चकितिसा आयोग](#)
- [पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम](#)
- [जननी शशि सुरक्षा कार्यक्रम \(JSSK\)](#)
- [राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम \(RBSK\)](#)

नषिकरष:

- वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि हो रही है, आयुषमान भारत जैसे सरकारी कार्यक्रमों से नागरिकों का स्वास्थ्य व्यय कम हो रहा है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव एवं दुर्गमता जैसी चुनौतियाँ अभी भी व्याप्त हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुँच सुनिश्चित करना एवं स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना वास्तविकता में सुदृढ़ एवं समतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न :

भारत में बढ़े हुए हेल्थकेयर फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मशिन' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना।
2. छोटे बच्चों, कशिरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों को कम करना।
3. बाजरा, मोटे अनाज और बनिा पॉलशि कयि चावल की खपत को बढ़ावा देना।
4. पोल्टरी अंडे की खपत को बढ़ावा देना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) केवल 3 और 4

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय पोषण मशिन (पोषण अभियान) महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो आँगनवाड़ी सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ-भारत मशिन आदि जैसे वभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभसिरण सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय पोषण मशिन (NNM) का लक्ष्य 2017-18 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के दौरान 0-6 वर्ष के बच्चों, कशिरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। अतः कथन 1 सही है।
- NNM का लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और कशिर लड़कियों के बीच) को कम करना तथा बच्चों के जन्म के समय कम वजन की समस्या को दूर करना है। अतः कथन 2 सही है।
- NNM के तहत बाजरा, बनिा पॉलशि कयि चावल, मोटे अनाज और अंडों की खपत से संबंधति ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन 3 और 4 सही

नहीं है।

?????:

प्रश्न. “एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।” विश्लेषण कीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/07-05-2024/print>

